**दिसम्ब0र, 2017 के दौरान, गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वdपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वRपूर्ण कार्यक्रम**

वर्ष 2017 में बाढ़/भूस्खरलन/सूखा से प्रभावित मिजोरम, मणिपुर और केरल राज्यों ा के लिए केन्द्री□य सहायता हेतु दिनांक 13.12.2017 को माननीय गृह मंत्री की अध्य,क्षता उच्चे स्त रीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

2. भारत-बांग्लाैदेश की सीमा (आईबीबी) से लगे राज्यों् के मुख्यचमंत्रियों के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए माननीय गृह मंत्री की अध्ययक्षता में कोलकाता में दिनांक 07.12.2017 को बैठक आयोजित की गई।

3. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्योंक में विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 29.12.2017 को माननीय गृह मंत्री ने विभिन्नब मुख्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की।

4. केन्द्री□य गृह सचिव ने दिनांक 1-2 दिसम्बुर, 2017 को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया तथा केन्द्रीीय मंत्रियों, सेना तथा केन्द्री□य सशस्त्रम पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और राज्यर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। केन्द्री□य गृह सचिव ने किबीथू में भारत-तिब्बात सीमा पुलिस की सीमा चौकी का भी दौरा किया तथा भारत-तिब्बवत सीमा पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत की।

5. राष्ट्री□य कार्यकारी की उप-समिति ने वर्ष 2017 में आई बाढ़ के फलस्वीरुप बिहार राज्य के लिए केन्द्री□य सहायता पर विचार किया।

6. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में कौशल विकास स्की म तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के त्विरत कार्यान्वलयन के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्रा, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्य् सचिवों को इस माह के दौरान परामर्शी-पत्र जारी किए गए।

7. इस माह के दौरान, आईएसआईएस ऑपरेटिव की गिरफ्तारी और प्रत्याइवर्तन के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत दो अभियुक्तों□ के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने हेतु अभियोजन की स्वी)कृति प्रदान की गई।

8. सम्पूतर्ण नागालैंड राज्य  को दिनांक 30.12.2017 से छः माह की अवधि के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ''अशांत क्षेत्र'' घोषित किया गया है।

9. केन्द्रीय सशस्त्रं पुलिस बलों के प्राधिकार, संभारण और व्य'य हेतु 38.7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

10. दिनांक 07.12.2017 को, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाईअड्डे को प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी (आईसीपी) के रूप में घोषित करने और पुलिस उपायुक्त , विजयवाड़ा, जिला कृष्णां को ''नागरिक प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त करने के बारे में अधिसूचना जारी की गई। विशाखापट्टम हवाईअड्डे पर दिनांक 13.13.2017 से ई-वीजा स्कीरम भी कार्यान्वित की गई है।

11. तिब्बमती शरणार्थियों के लिए ठहरने एवं यात्रा संबंधी विनियमों को सुचारू बनाया गया है तथा अनुपालन के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को निर्णय संसूचित कर दिए गए हैं।

12. सक्षम प्राधिकारी ने 1000 आप्रवासन सहायकों की संविदात्मोक आधार पर नियुक्ति, 350 चौकियों को उच्चीतर से निम्न तर ग्रेड में परिवर्तन तथा आसूचना ब्यूररो एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों को शामिल करके संविदात्म क आधार पर पूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए और अधिक दायरा प्रदान करने के लिए आप्रवासन ब्यूपरो को अनुमोदन प्रदान किया है।

13. मंत्रालय ने भारत में अफगान राष्ट्रिकों के लिए ठहरने संबंधी वीजा/निवासीय परमिट/दीर्घकालिक वीजा नीति को अंतिम रूप दिया है।

14. इस माह के दौरान, स्वापपक नियंत्रक ब्यू रो ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकीन और अन्यस स्वानपकों को जब्तद किया। ड्रग के दुर्व्यायपार के संबंध में एक वेनुजुएलाई राष्ट्रिक सहित 26 व्यकक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

15. आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडियों और अन्या सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 तथा दिव्यांबग व्यऔक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्रशासक/उप राज्यपाल को राज्यद सरकार की शक्तियों एवं कार्यों के प्रत्या योजन के बारे में अधिसूचनाएं सभी संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई हैं।

16. 23 मामलों में केन्द्रीकय सशस्त्रो पुलिस बलों के निकटतम रिश्तेदार को अनुग्रह मुआवजा राशि के रूप में 6.33 करोड़ रुपए की राशि स्वी कृत की गई है।

17. सीआईएसएफ परिसर (विशेष सुरक्षा समूह) (एसएसजी), ग्रेटर नोएडा में केन्द्रीय विद्यालय की स्थाएपना हेतु केन्द्रीमय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए पांच एकड़ भूमि का अनुमोदन दिनांक 22.12.2017 को प्रदान किया गया।

18. अवसंरचना के निर्माण हेतु 369.84 करोड़ रुपए की राशि की स्वीककृति भारत-तिब्बनत सीमा पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल को प्रदान की गई।

19. कानून एवं व्यषवस्थाा संबंधी ड्यूटियों और विभिन्न त्यौिहारों के लिए अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली , गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय एवं कर्नाटक राज्योंी में केन्द्रीय सशस्त्रल पुलिस बलों की 116 कंपनियां तैनात की गईं।

20. असम में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टार तैयार करने, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में नगर निगम और विधान सभा चुनाव संबंधी ड्यूटियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्री य सशस्त्रं पुलिस बलों की 113 कंपनियां तैनात की गईं।

21. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत जम्मूो एवं कश्मीकर राज्य् को इस माह के दौरान, 17.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिससे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई कुल राशि 74.24 करोड़ रुपए हो गई है।

* * * * *